इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सरकार ध्यान दे और एक वक्तव्य इस स्थिति पर दे सदन के सामने, ताकि वह स्थिति देश के सामने आ सके। आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Plight of the retrenched employees of Auto Tractors Ltd., Pratapgarh and company's sale to a private party

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार हूं कि मुझे आपने एक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर विशेष उल्लेख करने का मौका दिया है। उत्तर प्रदेश में, जब पिछले दिनों मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और चन्द्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, ...(व्यवधान) ...उस समय की एक घटना की ओर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। इसी सदन में मैंने उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम का एक मामला उठाया था और आज मुझे यह कहने में खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरसिंह राव जी के पार्टिसिपेशन आफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट की नई औद्योगिक नीति के तहत, उनके निर्देश पर, उनके दबाव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने संजय डालमिया से लेकर, जो एक करोड़ रुपए में कारखाना बेचा गया था 725 करोड़ जिसका अब दाम लगा था, पुन: उसका सरकारीकरण कर लिया है। दो कारखाने और उस शासन-काल में बेचे गए—एक आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में और दूसरा स्कूटस इंडिया लिमिटेड लखनऊ में। ये दोनों कारखाने उत्तर प्रदेश सरकार ने इंदिरा जी के निर्देश पर लगाए थे और हजारों मजदूर इसमें काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में ऑटो ट्रैक्टर्स के कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्पीड़न हो रहा है, उनकी दुर्दशा हो रही है और उत्पीड़न हो रहा है, वे पीड़ित हैं और न्याय पाने के लिए जगह-जगह भटक रहे हैं। ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में ट्रैक्टर्स तथा डीजल इंजन बनाने की एकमात्र इकाई थी। इसमें 1294 कर्मचारी कायरत थे। कम्पनी द्वारा बनाए गए डीजल इंजनों की मांग देश-विदेश में सर्वत्र थी। पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने समस्त श्रमिकों कानूनों की अवहेलना करते हुए 21 नवम्बर, 1990 को रातों-रात कारखाने को बंद कर केवल एक कार्यालय आदेश द्वारा समस्त कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया। पिछले 13 महीनों से कर्मचारियों पर आश्रित 10,000 लोगों में भुखमरी फैली हुई है। उनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। कर्मचारियों के परिवार के साथ-साथ बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। तीन कर्मचारी दवा के अभाव में मर गए हैं और दो कर्मचारी मौत के घाट पर खड़े हैं। कारखाने को बंद करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही की और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश के द्वारा जो इस कारखाने को बेचने से मनाही की थी, उसकी अवहेलना की और उसके विक्रय पर स्थगन आदेश की अवमानना करके कारखाने को 21 मार्च, 1991 को निजी क्षेत्र की सिपानी ऑटोमोबाइल्स, बंगलौर नामक कम्पनी को एक करोड़ रुपए में बेच दिया गया। कर्मचारियों द्वारा विरोध करने पर उन पर डंडे बरसाए गए, आंसू गैस छोड़ी गई और अगर कर्मचारी विवेक से काम न लेते तो सैंकड़ों लोग मौत के घाट उतर जाते। 21 मार्च, 1991 को प्रतापगढ़ फैक्टरी के मुख्य द्वार पर यह चिंतनीय घटना हुई। मैं बताना चाहता हूं इस सदन को कि 152 एकड़ जमीन पर लगे आधुनिक प्लांट एवम् मशीनरी तथा 402 मकानों की कालोनी समेत लगभग 100 करोड़ रुपयों की सम्पत्ति वाले कारखाने को मात्र एक करोड़ रुपए में बंगलौर के आर०के० सिपानी नामक पूंजीपति को बेच दिया गया।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे जितने सरकारी कारखाने थे, उनको बेचा जा रहा है। ऑटो ट्रैक्टर्स के सारे कर्मचारी अपने लिए न्याय पाने के लिए, माननीय सभापति जी, आप

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

न्याय के आसन पर बैठे हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे यहां भी आए थे, सत्या बहिन के यहां भी गए थे, मुझे पता लगा है कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के यहां भी गए थे, हर जगह जा रहे हैं। ...(**समय की घंटी**)...मैं दो मिनट और लूंगा सर। 2.10.91 से लखनऊ में विधान सभा के सामने वे अनिश्चित-कालीन धरने पर बैठे हैं और 22 अक्तूबर, 1991 से सारे कर्मचारी एवम् उनके परिवार आंदोलन कर रहे हैं और तब तक वे आंदोलन को वापिस नहीं लेंगे जब तक कि इस कारखाने को सरकार फिर नहीं ले लेती है। दिनांक 22 अक्तूबर से अब तक 600 कर्मचारी उन्नाव, रायबरेली की जेलों में बंद कर दिए गए हैं और उनके दुध-मुंहे बच्चे दाने-दाने को तरस रहे हैं, यह मुझे पता लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय को मैंने इस सदर्भ में 21 नवम्बर को पत्र लिखा था और उन्हें 15 दिन का समय दिया था कि 15 दिन में सिपानी सेठ को जो यह एक करोड़ रुपए में कारखाना बेच दिया गया है, उसको आप रोकें। एक कन्वेंशन बन चुका है, "डाला" सीमेंट फैक्टरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिग्रहीत किया है, उसी तरह इसको भी अधिग्रहीत करे और सारे शेयर आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास हैं। मुझे नहीं लगता कि सिपानी सेठ बी०जे०पी० का ट्रेज़रार है, तो फिर किस दबाव में कल्याण सिंह जी इसको नहीं कर रहे हैं? इस संदर्भ में भारत के प्रधान मंत्री को भी 21 नवम्बर को मैंने पत्र लिखा है, जिसका जवाब अभी मेरे पास नहीं आया है। वे इस संबंध में कार्रवाई कर रहे होंगे। मजदूरों की

3.00 P.M.

जो मांग है उसमें ऑटो ट्रेक्टर्स लि० और सिपानी के मध्य हुये अनुबन्ध को अविलम्ब रद्द किया एवं कम्पनी का डाला, चुर्क और चुनार के सीमेंट कारखानों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण करके 1294 कर्मचारियों को रोजगार दिया जाये सरकार के द्वारा, न कि सेठ के द्वारा। नवम्बर, 1990 से बकाया 13 माह की तनख्वाहें उनके दी जाये। प्रबन्धन में श्रमिकों की भागी-दारी सुनिश्चित करके कारखाने को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अच्छी तर् से चलाया जाये। सिपानी सौदे में भयानक घपला हुआ है और पचास करोड़ का लेनदेन हमारी केन्द्र सरकार के प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री ने किये हैं। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि इसकी जांच कराये और अंत में, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यदि उत्तर प्रदेश सरकार ... (**व्यवधान**)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : कौन प्रधान मंत्री थे?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : चन्द्रशेखर जी जब प्रधान मंत्री थे, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। शुरू में ही मैंने कहा, बार-बार नाम लेने से कमल मोरारका जी खड़े हो जायेंगे, क्योंकि अभी चन्द्रशेखर जी के प्रति उनका मोह नहीं टूटा है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA) : You have made your point.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : यदि उत्तर प्रदेश सरकार ऑटो ट्रेक्टर्स लि० को चलाने में असमर्थ है तो भारत सरकार से मेरा अनुरोध है, मंत्री महोदय यहां बैठे हुये हैं, कि इस कारखाने को भारत सरकार के प्रतिष्ठान एच०एम०टी० के साथ सम्बद्ध कर दिया जाय, जैसे सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया से मैंने मांग की थी। मैं विश्वास करता हूं कि यह कारखाना फिर सरकारी हाथों में होगा और टैक्नीक सहायता देकर के, सला दे करके 98 प्रतिशत मशीनें यहां एच० एम०टी० की हैं और एच०एम०टी० ट्रेक्टर्स उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर

चौबिस हजार प्रति वर्ष यहां के मजदूर करना चाहते हैं। इसलिये मेरी मांग है कि जो पिछली सरकारों ने, नरसिंह राव की न्यू इंडस्ट्रियल पौलिसी तब तक सफल नहीं होगी मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि जो पिछली दोनों सरकारों ने प्राईवेटाइजेशन के नाम पर अरबों-करोड़ों रुपया घूंस लेकर के इस देश के सरकारी कारखानों को बेचा है। ग्रॉटो ट्रेक्टर्स के 1294 मजदूरों और दस हजार परिवार के जीवन-मरण का प्रश्न है और यह प्रश्न हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है... (व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : I also associate myself with it.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : डाला सीमेंट कारखाने का हमने सरकारीकरण कराया है। इसलिये हम विश्वास करते हैं कि मेरी प्रार्थना पर उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार ध्यान देगी और इन मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होगा।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय रत्नाकर पाण्डेय जी ने जो ग्रॉटो ट्रेक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ के संबंध में स्पेशल मेंशन के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों को सदन में रखा और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। महोदय, एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1989 में इस ग्रॉटो ट्रेक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ का उद्घाटन मेरी चेयरमेनशिप प्रेजीडेंटशिप में हुआ था। एक कल्पना थी कि प्रतापगढ़ जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस ट्रेक्टर के कारखाने की वजह से जहां लोगों को काम मिलेगा, वहीं पर औद्योगिक विकास होगा। लेकिन धीरे-धीरे जो स्थिति पैदा हुई है वह पूरी खतरनाक है। इसलिये जो 1294 कर्मचारी हैं तथा उनके साथ और भी जो परिवार उनसे जुड़े हुये हैं, यह लोग जो भुखमरी के कगार पर आज आ गये हैं और आंदोलन चल रहा है तथा कर्मचारियों को जेल में भी ठूंस दिया गया है। अतः कर्मचारियों की जो मांगें हैं जिनका उल्लेख माननीय रत्नाकर पाण्डेय जी ने किया है, उन पर सहानुभूति से सरकार जल्दी ध्यान दे और ग्रॉटो ट्रेक्टर्स लि० का अधिग्रहण सरकार स्वयं करे और करके उसको चलाने की व्यवस्था करे, ताकि प्रतापगढ़ का विकास न रुके और कर्मचारियों का भी मामला हल हो, औद्योगिक वातावरण को भी कोई नुकसान न पहुंचने पाये और जो सरकारी पूंजी लगी हुई है वह भी न जाने पाये।

श्रीमती सावा बहिन (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुये कहना चाहती हूं कि ग्रॉटो ट्रेक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ के कर्मचारियों ने मुझे पत्र लिखा था और मैंने स्वयं लखनऊ जाकर उनकी दुर्दशा को देखा था। इस संबंध में मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था। लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं क्या होने जा रहा है? हम आज तक इंतजार कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA) : You want to associate with it ? It is recorded.

श्रीमती सावा बहिन : मेरा निवेदन है सदन के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को जो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, उनके परिवार, बच्चों और महिलाओं को, मान्यवर, तत्काल सहायता की जरूरत है। उनको अन्तरिम सहायता दी जाये और इस संबंध में तुरंत कदम उठाये जायें।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं डा० रत्नाकर पाण्डेय जी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुये आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि ग्रॉटो ट्रेक्टर्स लि० में काम करने वाले इन 1294 कर्मचारियों को नवम्बर, 90 से वेतन दिया जाये और साथ ही ऐसी कई भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, जो चन्द्रशेखर जी के समय डील्स हुई

[श्रीमती सत्या बहिन]

थी। इसलिये उस दौरान जितने भी गवर्नमेंट के कारखानों को निजी औद्योगिक घरानों को दिया गया, उन सब की जांच सरकार को करनी चाहिये, ऐसा मेरा निवेदन है।

SHRI SHANTI TYAGI (Uttar Pradesh): I alsoassociate myself with it.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA) : Mr. Shanti Tyagi, you also associated. It is all right.

Leakage of Narasimhan Committee report on Banking

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh) : Sir, it is a fact that all the nationalised banks are in a very bad shape and they are not functioning well. The recovery rate is at its lowest ebb and corruption is rampant. And M. Ds., Chairman and higher officials are ganged up with industrialists and other big heads. Instead of recovering the loans, they are pumping more money, under the guise of rephasing and rescheduling the loans, in sick mills and the like. The Government, in its wisdom, has appointed the Narasimhan Committee to go in to the working of the nationalised banks and, I believe, the Committee has submitted its report. But the Government did not think it proper to publish the report of the Committee; nor did they seek any debate on the same from the public; nor the was report tabled in either of the Houses of Parliament. However, it is suprising that day in and day out, the report of the Committee is getting published in all the newspapers without any exception, in the full text. I do not know how the entire report finds its way to the columes of various newspaers without the Government publishing it. And the Government is so foolish that it never publishes it: not does it allow any debate; nor does it own the reports already published in newspapers.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI M.L. FOTEDAR) : Sir, the hon. Member should be abit discreet. He should withdraw the word 'foolish'.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: I would like to advise the Government to see that some action is taken against the wholesale....(*Interruption*).

SHRI M. L. FOTEDAR: Sir, let him withdraw the word.

SHRI KAMAL MORARAKA (Rajasthan): 'Not sensible'. That is what he means.

SHRI M. L. FOTEDAR: He may say 'not proper'.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Not sensible, not wise.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): He may even say 'not intelligent'.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: I hope that the Government will place the the report on the Table of the House after some time. There is no point in informing Parliament after getting it circulated through millions and millions of copies of newspapers throughout the length and breadth of the country. So, I would like to seek a clarification from the Government as to what happened and how the Government failed to protect the report and how it was leaked to the press, to the media, in full text. Thank you.

Government's move to hand over Evaluation of Customs Duty to a Multi-Natioal Swiss Company

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the hon. House to a multi-national company entering into the field of even evaluating the excise duty in this country.

Sir, a news item appearing in the 'Sunday Observer' says that the Government is poised to hand over the evaluation of customs duty to a Swiss-based company called 'Society General of Surveillance'. The reason given by them is that in the economic package that was discussed among the Government, the IMF and the World Bank, this was one of the items figuring. The Government's assessment is that they are losing more than Rs. 2000 crores every year by way of under-invoicing by importers and misclarification of import items. Therefore, the Government has invited the Swiss-based company for a trade-facilitation programme. That is, whenever any importer wants to import any goods, the quantity and quality of the items are subject to check-up by the authority including the price-checking. One per cent commission has been agreed to be given to that company. There is considerable dissension in the minds of Customs officials. They feel that they have been sidelined and made to be a rubber stamp. After evaluation, when everything has been done by this authority, they have to put a rubber stamp for formality's sake. It is quite disheartening to note that this programme of hand ling over the evaluation of Customs duty to this authority has been done in a hasty